हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 19 अप्रैल 2025, समय 1305 (5 मिनट)

भारत ने कहा है कि वह समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ कृषि के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कल ब्राजील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक छोटे किसानों को संरक्षित और सशक्त नहीं किया जाता तब तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य अधूरे रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लिए महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना एक मिशन है। श्री चौहान ने कहा कि भारत के लिए कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए आजीविका, भोजन और सम्मान का स्रोत है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 51 करोड़ छोटे किसान वैश्विक खाद्य प्रणाली की रीढ़ हैं और जलवायु परिवर्तन, मूल्य अस्थिरता और संसाधनों की कमी के कारण सबसे कमजोर भी हैं। बैठक के दौरान, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने भूमिसक्षरण, मरुस्थलीकरण और मिट्टी की उर्वरता में कमी की समस्या से निपटने के लिए ब्रिक्स भूमि पुनरुद्धार साझेदारी का शुभारंभ किया। संयुक्त घोषणापत्र में, ब्रिक्स देशों ने सामूहिक रूप से वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली को निष्पक्ष, समावेशी, नवीन और टिकाऊ बनाने के अपने संकल्प को दोहराया।

****

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी -एनटीए ने आज सुबह संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन 2025 के दूसरे सत्र के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार, कुल 24 छात्रों ने बीई/बीटेक में दाखिले के लिए 100 प्रतिशतता स्कोर हासिल किया है। कट-ऑफ के साथ परिणाम अब आधिकारिक जेईई मेन वेबसाइट - jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध है। इस साल जेईई मेन जनवरी और अप्रैल में दो बार आयोजित किया

गया । यदि कोई उम्मीदवार दोनों सत्रों में उपस्थित हुआ है, तो अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जेईई मेन में उम्मीदवार के सर्वश्रेष्ठ स्कोर पर विचार किया जाएगा।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए आने वाले दिनों में हरियाणा को विनिर्माण केंद्र बनाया जाएगा।मुख्यमंत्री कल गुरुग्राम के मानेसर स्थित भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट उपरांत बैठक को संबोधित कर रहे थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने। इस लिए इस बार के बजट में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के बजट को बढ़ाकर 1,848 करोड़ 12 लाख रुपए कर दिया है जोकि पिछली बार की तुलना में 129 फीसदी ज्यादा है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण व मेक इन हरियाणा के उद्देश्य के साथ औद्योगिक नीतियों को केंद्र में रख कर हरियाणा प्रदेश एक विनिर्माण केंद्र बनेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में औद्योगिक श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 300 अटल किसान श्रमिक कैंटीन खोली जाएंगी ताकि उन्हें उचित दर पर पौष्टिक भोजन मिल सके।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 3 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए शुरू की गई "चिरायु आयुष्मान भारत योजना"

का का विस्तार कर दिया है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने घोषणा बताया कि संशोधित योजना के तहत, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार अब 4,000 रुपये का वार्षिक अंशदान देकर योजना का लाभ उठा सकेंगे । इसी प्रकार 6 लाख रुपये से अधिक आय वाले परिवार 5,000 रुपये का वार्षिक अंशदान देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।इससे पहले, परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1लाख 80 हजार और 3 लाख रुपये के बीच आय वाले परिवार ही सालाना 1,500 रुपये का योगदान देकर इस योजना का लाभ उठाने के पात्र थे।यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिससे लाभार्थियों को राज्य भर में सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त करने में मदद मिलती है।

****

सरकार ने दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की दावेदारी को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार बताया है। एक वक्तव्य में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया की सरकार का फिलहाल इस तरह के प्रस्ताव का कोई विचार नहीं है।इसमें कहा गया है कि जीएसटी केवल मर्चेंट डिस्काउंट रेट-एमडीआर जैसे शुल्कों पर लगाया जाता है, जो कुछ उपकरणों का उपयोग करके किए गए भुगतान से संबंधित होते हैं। मंत्रालय ने कहा की जनवरी 2020 से प्रभावी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी ने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से व्यक्ति द्वारा व्यापारी को किये गये यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट - एमडी आर को हटा दिया है।

****